(c) Control and supervision of prices of foodgrains are exercised by the State Governments through the normal administrative machinery set up by them for the enforcement of various food control Orders.

दिल्ली जल सम्पूर्ति योजना की स्वीकृति

2719. **श्री माधव राव सिंधिया :**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की अपर गंग नहर से लगभग 200 क्यूसेक जल की सप्लाई मुरादनगर से दिल्ली लाने की 'दिल्ली जल सम्पूर्ति योजना" की जांच और स्वीकृति किस-किस स्तर पर कब-कब तथा किन अधिकारियों द्वारा की गई ;

(ख) इस योजना पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग कितना व्यय हो चुका है और उसके परिणामस्वरूप कितना कार्य पूरा हो चुका है ;

(ग) इस योजना की क्रियान्विति के लिए इस समय कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भीम सेहता) : (क) उत्तर प्रदेश की अपर गंग नहर से दिल्ली को 200 क्यूसेक जल सप्लाई की एक योजना दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन के परामर्श से सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय और निर्माण और आवास मंत्रालय के विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश के स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग को सर्वेक्षण, अन्वेषण, तकनीकी अध्ययन, डिजाइन तथा निर्माण कार्य सौंपा गया है। उन्होंने परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह परियोजना जिसमें दिल्ली को जल लेजाने के लिए जल वाहिनी तथा अन्य साधनों के संरेखण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली नगर निगम को 170 लाख रुपये (1972–73 वर्ष में 20 लाख तथा 1973–74 वर्ष में 150 लाख रुपये) दिल्ली प्रशासन के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रिम के रूप में दिये हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया व्यय निम्नलिखित है :—

	लाख रुपये
1972–73	4.05
1973–74	43.25
1974–75 (जून, 74 तक)	14.50
	61.80

किये गये कार्य का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) मुख्य इंजीनियर, उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लगाये गये कर्मचारियों की स्थिति निम्नलिखित है :—

अधिकारी 25

कर्मचारी 185 (इसमें कार्य प्रभारित स्थापना पर निगरानी और पहरा आदि जैसे अनिवार्य पदाधिकारी शामिल नहीं हैं) :

(घ) अपर गंग नहर से जल सप्लाई के वैकल्पिक प्रस्तावों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है जिसमें दिल्ली प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन, हरियाणा सरकार, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग तथा पर्यावरणीय संस्थान और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हैं। आशा है कि यह दल अपने निर्णयों को अन्तिम रूप शीघ्र दे देगा ।

विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग ने इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु गाजियाबाद में दिसम्बर, 72 में एक स्वतन्त्र परिमण्डल तथा छः मण्डलों की स्थापना की। स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण, अन्वेषण, अभिकल्पन कार्य तथा तकनीकी अध्ययन करने के पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा प्राक्कलन तैयार किये गये थे। कार्य-निष्पादन सम्बन्धी आरम्भिक तैयारी पूर्ण हो चुकी है । भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया है । पर्याप्त सामग्रियों का प्रबन्ध किया गया है अथवा उनके आदेश दे दिये गए हैं। विभिन्न मशीनरियों/उपकरणों के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य कार्य के निष्पादन के निविदा सम्बन्धी कागजात देने के लिए तैयार है । नींव सम्बन्धी अन्वेषण किये जा चुके हैं तथा निर्माण के नक्शो को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। स्टाक यार्ड, गैर-रिहायशी तथा रिहायशी आवास आंशिक रूप से पूर्ण हो गये हैं।

Reduction in Sugar Quota of States

2720. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether sugar quota of the States has been reduced; and

(b) if so, the reasons thereof and the extent of cut in quota of each state?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI B. P. MAURYA): (a) and (b). On account of a decline in the estimated production and the decision to export 5 lakh tonnes of sugar to earn the much needed foreign exchange, the total release of levy sugar had to be reduced to 1.90 lakh tonnes for June, 1974 and to 1.80 lakh tonnes per month from July, 1974 onwards from the previous level of 2 lakh tonnes per month during January to May, 1974. A statement showing the monthly allotments of levy quota of sugar to States from January to August 1974 is laid on the Table of the Sabha [*Placed in Library. See* No. LT-8219/74]

Membership of the C.P.W.D. Industrial Workers Co-operative Thrift and Credit Society Ltd.

2721. SHRI BHOLA MANJHI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the membership of the C.P.W.D. Industrial Workers Co-operative Thrift and Credit Society Ltd., is open only to the industrial workers of the C.P.W.D.;

(b) whether Clerical staff of C.P.W.D. do not fall in the category of industrial workers; and

(c) if so, the number of clerks of C.P.W.D., who are members of this society and the reasons for allowing them to continue as members of the society?